

## दिल्ली उच्च न्यायालय ने गर्भपात की मंजूरी का आदेश वापस लिया

### प्रलिस के लिये:

गर्भ का चिकित्सकीय समापन, [गर्भ का चिकित्सकीय समापन \(MPT\), संशोधन अधिनियम 2021](#), अनुच्छेद 21 का दायरा, सुचिता श्रीवास्तव बनाम चंडीगढ़ प्रशासन मामला, रो बनाम वेड मामला ।

### मेन्स के लिये:

भारत में गर्भ के चिकित्सकीय समापन की स्थिति, गर्भ का चिकित्सकीय समापन (MPT), संशोधन अधिनियम 2021 की मुख्य विशेषताएँ ।

[स्रोत: द हट्टि](#)

### चर्चा में क्यों?

हाल ही में [दिल्ली उच्च न्यायालय](#) ने अपने उस आदेश को वापस ले लिया है जिसमें **26 वर्षीय महिला** को 29 सप्ताह के गर्भ को समाप्त करने की अनुमति दी गई थी ।

- न्यायालय ने अब [अजनमे बच्चे](#) के जीवन के अधिकार की वकालत करते हुए महिला को एम्स या किसी केंद्रीय या राज्य अस्पताल में प्रसव कराने का निर्देश दिया है ।

### भारत में गर्भ के चिकित्सकीय समापन की स्थिति क्या है?

- ऐतहासिक परिप्रेक्ष्य:** 1960 के दशक में, बड़ी संख्या में प्रेरित गर्भपात के मद्देनजर केंद्र सरकार ने देश में गर्भपात को वैध बनाने पर विचार-विमर्श करने के लिये शांतलाल शाह समिति का गठन किया ।
  - इसकी सिफारिशों के परिणामस्वरूप **गर्भ का चिकित्सकीय समापन (MPT) अधिनियम, 1971 अधिनियमित** किया गया, जिससे महिलाओं के स्वास्थ्य की रक्षा और मातृ मृत्यु दर में कमी लाने के लिये सुरक्षा तथा कानूनी गर्भपात की अनुमति दी गई ।
- MTP अधिनियम और संशोधन:**
  - MTP अधिनियम, 1971** लाइसेंस प्राप्त चिकित्सा पेशेवरों को महिलाओं के स्वास्थ्य की रक्षा और मातृ मृत्यु दर को कम करने के लिये विशेष पूर्व निर्धारित स्थितियों (जैसा कि कानून के तहत प्रदान किया गया है) में **सुरक्षा तथा कानूनी गर्भपात** करने की अनुमति देता है ।
    - इसमें [गर्भ का चिकित्सकीय समापन \(MPT\), संशोधन अधिनियम 2021](#) के माध्यम से बाद में संशोधन किया गया ।
- गर्भ के समाप्त के प्रावधान:**

गर्भाधान के बाद से समय	MTP अधिनियम, 1971	MTP (संशोधन) अधिनियम, 2021
12 सप्ताह तक	एक चिकित्सक की सलाह पर	एक चिकित्सक की सलाह पर
12 से 20 सप्ताह	दो चिकित्सकों की सलाह पर	एक चिकित्सक की सलाह पर
20 से 24 सप्ताह	अनुमति नहीं	वैशेष श्रेणी की गर्भवती महिलाओं के लिये दो चिकित्सकों की सलाह पर
24 सप्ताह से अधिक	अनुमति नहीं	भ्रूण में गंभीर असामान्यता के मामले में मेडिकल बोर्ड की सलाह पर अनुमति
गर्भावस्था के दौरान किसी भी समय	गर्भवती महिला की जान बचाने के लिये यदितुरंत आवश्यक हो तो किसी डॉक्टर की सलाह पर	गर्भवती महिला की जान बचाने के लिये यदितुरंत आवश्यक हो तो किसी डॉक्टर की सलाह पर

**नोट:** MTP संशोधन अधिनियम, 2021 के तहत महिलाओं की विशेष श्रेणियों में [बलात्कार पीड़िता](#), [यौन शोषण की शिकार](#) एवं अन्य कमजोर महिलाएँ जैसे [द्विआंग और नाबालग](#) शामिल हैं ।

■ **MTP संशोधन अधिनियम, 2021 की अन्य मुख्य विशेषताएँ:**

- **गर्भनरोधक वधि या उपकरण की वफिलता के कारण गर्भपात:** MTP अधिनियम ने ववाहति महिलाओं को गर्भनरोधक वधि या उपकरण की वफिलता के मामले में 20 सप्ताह तक के गर्भ को समाप्त करने की अनुमति दी है।
  - MTP संशोधन अधिनियम ने **अववाहति महिलाओं के लयि भी अनुमोदन में वृद्धि** की है।
- **मेडकिल बोर्ड:** बोर्ड महत्त्वपूर्ण भ्रूण असामान्यताओं के लयि 24 सप्ताह से अधिक के गर्भधारण का आकलन करेगा।
  - इसमें स्त्रीरोग वशिषज्ज, बाल रोग वशिषज्ज और रेडयोलॉजिस्ट जैसे वशिषज्ज शामिल होने चाहयि तथा इसे सभी राज्य व केंद्रशासति प्रदेश सरकारों द्वारा स्थापति कयि जाएगा।
- **गोपनीयता उपाय:** एक पंजीकृत चकितिसक केवल वधि/कानून द्वारा अधिकृत व्यक्तियों को ही समाप्त गर्भपात के वविरण का खुलासा कर सकता है। **उल्लंघन पर एक वर्ष तक की कैद, जुर्माना या दोनों** का प्रावधान है।

■ **संवधानिक रुख:**

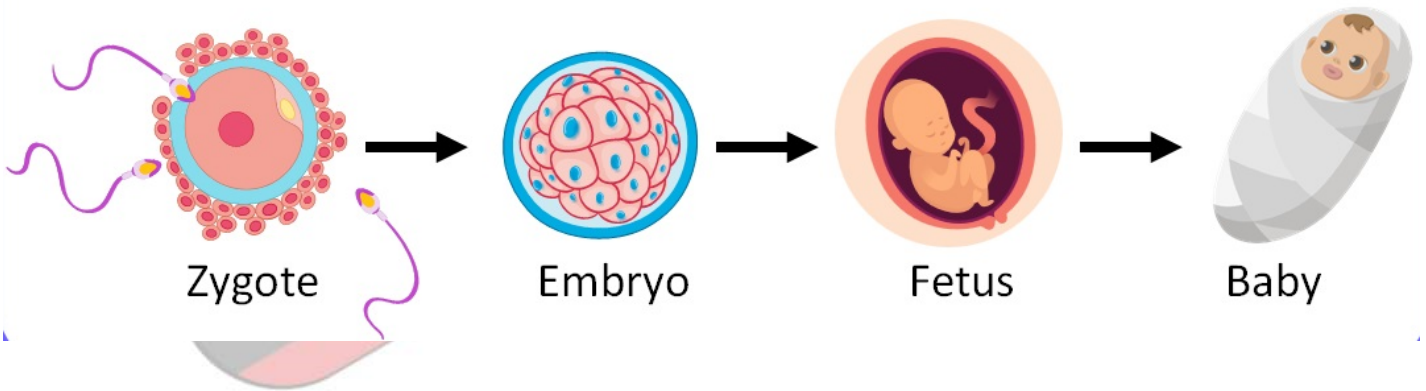
- हालाँकि **संवधान में गर्भपात के अधिकार का स्पष्ट रूप से उल्लेख नहीं** है, लेकनि कुछ मौलिक अधिकार **परजनन अधिकारों और महिलाओं की स्वास्थ्य देखभाल** से जुड़े हुए हैं।
- **अनुच्छेद 21 - जीवन और व्यक्तगत स्वतंत्रता का अधिकार:** सर्वोच्च न्यायालय ने परजनन स्वायत्तता और स्वास्थ्य देखभाल (21/22/23/24/25/26/27/28/29/30/31/32/33/34/35/36/37/38/39/40/41/42/43/44/45/46/47/48/49/50/51/52/53/54/55/56/57/58/59/60/61/62/63/64/65/66/67/68/69/70/71/72/73/74/75/76/77/78/79/80/81/82/83/84/85/86/87/88/89/90/91/92/93/94/95/96/97/98/99/100, 2009) को सम्मलिति करने के लयि इसकी व्यापक रूप से व्याख्या की है।
  - इसके अलावा, हाल ही में **सर्वोच्च न्यायालय** ने कहा कि **अजनमे बच्चे के अधिकारों को महिला के परजनन अधिकार के साथ संतुलति कयि जाना चाहयि**।

**नोट:** भारत में गर्भ की नैतिक स्थिति, वधिकि स्थिति तथा संवधानिक अधिकारों को लेकर अभी भी अनश्चितता है। हालाँकि **हिंदु उत्तराधिकार अधिनियम, 1956 की धारा 20** के तहत गर्भधारण की स्थिति से भ्रूण के जीवन की सुरक्षा का प्रावधान है।

■ **वैश्विक रुझान:**

- संपूर्ण वशिव में गर्भपात संबंधी कानूनों के उदारीकरण तथा गर्भपात सेवाओं तक पहुँच में बेहतरी की दशि में कार्य करने के प्रयास कयि जा रहे हैं।
- **1990** के दशक की शुरुआत से **वशिव स्तर पर लगभग 60 देशों ने गर्भपात कानूनों में ढील दी** है, जसिसे गर्भपात के लयि कानूनी आधार व्यापक हो गए हैं।
- वशिष रूप से केवल चार देशों- **संयुक्त राज्य अमेरिका, अल सालवाडोर, निकारागुआ तथा पोलैंड** ने उक्त अवधि के दौरान गर्भपात प्रक्रयि में कानूनी आधार को हटाकर गर्भपात कानूनों को और सख्त कर दयि है।
  - वर्ष 2022 में इस दशि में एक महत्त्वपूर्ण वकिस हुआ जब अमेरिकी सर्वोच्च न्यायालय ने गर्भपात के संवधानिक अधिकार को समाप्त कर दयि (**रो बनाम वेड मामला**)।

## ZYGOTE DEVELOPMENT



- **युग्मनज:** नषिचन के दौरान शुक्राणु तथा अंड के संलयन से बनने वाली प्रारंभिक कोशकि।
- **भ्रूण:** नषिचन के कषण से लेकर गर्भावस्था के लगभग 8वें सप्ताह तक वकिसा का प्रारंभिक चरण।
- **गर्भ:** प्रसवपूर्व वकिसा का बाद का चरण जो **नौवें सप्ताह से शुरू होकर शशि के जन्म** को संदर्भति करता है। इसी दौरान शशि के अंगों तथा प्रणालयों का वकिसा होता है।

## UPSC सविलि सेवा परीक्षा, वगित वर्ष के प्रश्न

??????????:

प्रश्न. भारत में समय और स्थान के वरिद्ध महिलाओं के लयि नरिंतर चुनौतयिँ क्या हैं? (2019)

PDF Refernece URL: <https://www.drishtias.com/hindi/printpdf/delhi-high-court-reverses-abortion-approval-order>

